ग्रोथ गिरने की वजह से टीसीएस में 85 प्रतिशत घट गईं नई नौकरियां

बेंगलुरु 12 जनवरी (ए)। कभी जॉब-क्रिएटिंग मशीन मानी जानेवाली देश की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टंसी सर्विसेज (टीसीएस) अब इस मोर्चे पर तेजी से कमजोर पड़ती जा रही है। कंपनी इस वित्त वर्ष के शुरुआती नौ महीनों में महज 3,657 नई नौकरियां ही दे पाई। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान दी गई नौकरियों के मुकाबले 85 प्रतिशत कम है जब 24,654 नौकरियां दी गई थीं। दरअसल, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कुछ वक्त से कहते आ रहे हैं कि कैपेसिटी के थोक में नई नौकरियां देना अब बीते दिनों की बात होती जा रही है क्योंकि कंपनियां खासकर नए युग की डिजिटल तकनीक के दौर में सामान्य कार्यों के लिए ऑटोमेशन लागू कर रही हैं और प्रमुख रूप से आला दर्जे के टैलंट को ही नौकरी पर रख रही हैं। टीसीएस के एग्जिक्युटिव वाइस प्रेजिडेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज के ग्लोबल हेड अजय मुखर्जी ने कहा, एक साल पहले हम अडवांस कंपिसिटी बिल्डिंग कर रहे थे। हमने 40,000 कैपेसिटीज ऑफर्स दिए। हमने अपने वर्कफोर्स में 78,912 लोगों को जोड़ा और कुल मिलाकर 33,000 से 34,000 अतिरिक्त नौकरियां दीं। हमारा ध्यान अब समय पर हायरिंग करने पर है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने नवंबर महीने में रिपोर्ट दी थी कि वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में टॉप छह इंडियन आईटी कंपनियों का वर्कफोर्स 13,402 घट गया जबकि पिछले साल की इसी अवधि में 60,240 अतिरिक्त वर्कफोर्स जुड़े थे। कंपनियों की ग्रोथ में मंदी इसकी बड़ी वजह है। टीसीएस ने गुरुवार को अर्निंग्स रिपोर्ट दी जिसमें उसका रेवेन्यू पिछली चार तिमाहियों में सबसे कम तेजी से बढ़ा है क्योंकि उसका फाइनैंशल सर्विस ऐंड इंश्योरेंस बिजनस नेगेटिव ग्रोथ में चला गया।

भ्रष्टाचार ने छीनी भारत में गांवों की सड़कें : अध्ययन

नई दिल्ली 12 जनवरी (ए)। भारत में सांठगांठ वाले भ्रष्टाचार के कारण दूर-दराज के इलाकों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली सड़कें संभवतः कभी तैयार नहीं हो सकेंगी, भले ही सरकार ने इसके लिए भुगतान कर दिया हो। एक अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है। अमरीका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय और फ्रांस के पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के शोधार्थियों ने भारत की प्रमुख सड़क निर्माण योजना 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)' के परीक्षण के लिए अनूठी तकनीक का उपयोग किया है। जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया है कि सड़क योजनाओं में सूचीबद्ध करीब 500 पक्की सड़कों के आंकड़ों के मुताबिक उनके लिए भुगतान कर दिया गया है कि लेकिन वे सड़कें कभी नहीं बनी। शोधकर्ताओं ने इन (गायब सड़कों) को राजनीतिक भ्रष्टाचार से जोड़ा है। उनका कहना है कि स्थानीय नेता अपने लोगों को सड़क निर्माण का ठेका देते हैं। शोध के प्रमुख व प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जैकब एन. शापिरो ने कहा, हमारे नतीजे संकेत देते हैं कि इस योजना में हुए भ्रष्टाचार से 8,57,000 ग्रामीणों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा है। उल्लेखनीय है कि इस योजना को वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सड़क-संपर्क से वंचित गांवों को बारहमासी (पक्की) सड़कों से जोड़ना था।

प्याज से आंखों में फिर आए 'आंसू'

नई दिल्ली 12 जनवरी (ए)। देश के कुछ भागों में प्याज की खुदरा कीमतें 50 से 60 रुपए किलो हो गई हैं। सरकार का कहना है कि यह मांग-पूर्ति में तात्कालिक अंतर के कारण है और खरीफ का प्याज आने के साथ महीने के अंत तक इसकी कीमतें कम हो जाएंगे। इस प्याज ने गृहिणियों की आंखों में फिर आंसू ला दिए हैं। दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता में प्याज 50 रुपए किलो के आसपास चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चेन्नई में भाव 45 रुपए है। छोटे कस्बों में भी प्याज का यही मिजाज है। कृषि सचिव एस.के. पटनायक ने बताया कि फसल वर्ष 2017-18 (जुलाई से जून) में प्याज पैदावार कुछ कम होने का अनुमान है लेकिन प्याज का कुल उत्पादन घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार रकबा घटने से फसल वर्ष 2017-18 में 4.5 प्रतिशत घटकर 2.14 करोड़ टन रहने का अनुमान है। पटनायक ने कहा कि आने वाले दिनों में प्याज की आवक बढ़ने के साथ प्याज की कीमतों में सुधार होगा। नासिक स्थित राष्ट्रीय बागवानी शोध एवं विकास फाऊंडेशन (एन.एच.आर.डी.एफ.) के कार्यकारी निदेशक पी.के. गुप्ता ने कहा, ''मौजूदा समय में खरीफ प्याज की आवक कम है।

मुकेश अंबानी लाएंगे अपनी खुद की करेंसी, बिटकॉइन को देगी टक्कर

जियो ने नवंबर में जोड़े 61.1 लाख नए कस्टमर, मार्केट शेयर बढ़कर13% हुआ

नई दिल्ली 12 जनवरी (ए)। फ्री वॉयस कॉलिंग और अनलिमिटेड 4जी डाटा देकर देश के टेलीकॉम सेक्टर को हिलाने के बाद अब रिलायंस जियो बिटकॉइन जैसी करेंसी को बाजार में उतारने जा रही है। जानकारी के मुताबिक रिलायंस जियो ने अपनी खुद की क्रिप्टोकरेंसी जियो कॉइन बनाने की योजना बनाई है। अंबानी जियो कॉइन प्रोजेक्ट की देखरेख करेंगे। इसके लिए आकाश अंबानी के नेतृत्व में 50 युवा पेशेवरों की एक टीम बनाई जाएगी। टीम में 25 साल के लोग शामिल होंगे। यह टीम जियो कॉइन के लिए ब्लॉकचेन तकनीक बनाएगी साथ ही इससे जुड़ी अन्य तकनीकी पहलुओं पर नजर रखेगा। बीते साल 2017 में बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में आई तेजी की वजह से सबी तरह की आभाषीय करेंसी काफी सुर्खियां बटोर चुकी हैं। दुनियाभर में लाखों लोगों ने क्रिप्टोकरेंसी में अपना पैसा लगा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रिलायंस जियो ने इस सेक्टर में उतरने की योजना बनाई है।

कोलकाता 12 जनवरी (ए)। रिलायंस जियो इंफोकॉम ने नवंबर में 61.1 लाख कस्टमर जोड़ते हुए अपना मार्केट शेयर 13 पर्सेंट तक कर लिया। इस दौरान उसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनी भारती एयरटेल ने 43.4 लाख, वोडाफोन इंडिया ने 27 लाख और आइडिया ने 31.9 लाख ग्राहक जोड़े। यह डेटा टेलिकॉम रेग्युलेटर ने जारी किया है। ट्राई की तरफ से जारी किए गए इन आंकड़ों के अनुसार, जियो का मार्केट शेयर 13.08 पर्सेंट हो गया है, जो पिछले साल अक्टूबर में 12.39 पर्सेंट, सितंबर में 11.72 पर्सेंट और अगस्त में 11.72 पर्सेंट था।

वहीं, इस दौरान भारती एयरटेल 28.953 करोड़ यूजर्स के साथ सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर बनी हुई है। मुकेश अंबानी की जियो के ग्राहकों की संख्या पिछले साल नवंबर के अंत में 15.2 करोड़ हो गई थी। वोडाफोन इंडिया के पास 21.102 करोड़ और आइडिया के पास 19.406 करोड़ कस्टमर थे। पब्लिक सेक्टर की भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने नवंबर में 10 लाख कस्टमर्स जोड़े। अब इसका मार्केट शेयर अक्टूबर के 9.03 पर्सेंट से बढ़कर 9.25 पर्सेंट हो गया है।

रिलायंस कम्युनिकेशन ने अक्टूबर में अपनी 2G और 3G वायरलेस सेवाएं बंद करके नॉन-मोबाइल बिजनेस चलाने की घोषणा की थी। ट्राई के सब्सक्राइबर्स डेटा से पता चलता है कि भारती एयरटेल का मार्केट शेयर बढ़कर 24.91 पर्सेंट, वोडाफोन इंडिया का 18.15 पर्सेंट और आइडिया का 16.69 पर्सेंट हो गया, जो अक्टूबर में क्रमशः 24.21 पर्सेंट, 17.68 पर्सेंट और 16.20 पर्सेंट था। मोबाइल नेटवर्क पर सक्रिय सब्सक्राइबरों की संख्या को बताने वाले प्रमुख मीट्रिक विजिटर लोकेशन रजिस्टर (वीएलआर) के मुताबिक, भारती के 99.23 पर्सेंट, वोडाफोन इंडिया के 94.87 पर्सेंट, आइडिया के 102.47 पर्सेंट और रिलायंस जियो के 81.45 पर्सेंट यूजर्स एक्टिव हैं। ट्राई के आंकड़ों से पता चलता है कि फोन कस्टमर्स का बेस घटकर 118.58 करोड़ रह गया है, जो नवंबर अंत तक 120.17 करोड़ था।

100 शहरों के लिए गैस डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की होगी नीलामी

नई दिल्ली 12 जनवरी (ए)। पेट्रोलियम एंड नैचरल गैस रेग्युलेटरी बोर्ड इस महीने 100 शहरों के लिए गैस डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की नीलामी करेगा। सरकार देश में नैचरल गैस का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का दायरा बढ़ने से परिवारों, फैक्ट्रियों और वीइकल की गैस की खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी।

डाउनस्ट्रीम रेग्युलेटर PNGRB इससे पहले देश के लगभग 80 शहरों के लिए गैस डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस दे चुका है। इससे पहले हुए सिटी गैस ऑक्शन में इंडस्ट्री ने अधिक दिलचस्पी नहीं ली थी। इसके अलावा लाइसेंस देने में देरी और पॉलिसी से जुड़ी रुकावटों के कारण लक्ष्य से कम संख्या में लाइसेंस दिए गए थे। देश में लगभग 1,282 कम्प्रेस्ड नैचरल गैस (सीएनजी) स्टेशन और लगभग 40 लाख डमेस्टिक पाइप्ड गैस कन्ज्यूमर हैं। PNGRB में एक वर्ष से अधिक समय से बोर्ड सदस्यों की पर्याप्त संख्या नहीं थे और इस वजह से लाइसेंस देने के फैसले में देरी हुई है। हाल ही में बोर्ड के खाली पदों को भरा गया है।

देश के अधिक शहरों में गैस की सप्लाइ पहुंचाने के लिए सरकार पाइपलाइंस बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि GAIL, ONGC, BPCL, इंडियन ऑयल और ऑयल इंडिया पूर्वोत्तर में एक गैस ब्रिड बनाने और इसे जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन से जोड़ने की मिलकर योजना बना रही हैं। इस पाइपलाइन का अभी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। GAIL 2,500 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का केंद्र की वित्तीय सहायता के साथ कंस्ट्रक्शन कर रही है। हालांकि, प्रधान ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स (DGH) को एक्सपर्ट्स के साथ एक इंडिपेंडेंट रेग्युलेटर बनाने की योजना से इनकार किया। उनका कहना था कि देश का अपस्ट्रीम सेक्टर अभी इसके लिए तैयार नहीं है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की टेक्निकल यूनिट DGH अपस्ट्रीम सेक्टर के रेग्युलेटर के तौर पर भी काम करता है, लेकिन इसने अपने कामकाज के लिए सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों से आए एंप्लॉयीज पर निर्भर करना पड़ता है। प्रधान ने पेट्रोल और डीजल की मार्केट प्राइसिंग का भी पक्ष लिया। उनका कहना था कि इन फ्यूल से कंट्रोल हटाने का फैसला काफी सोच-विचार के बाद किया गया था। पिछले कुछ महीनों से इंटरनेशनल रेट्स बढ़ने के कारण देश में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेज बढ़ रहे हैं।

मेक इन इंडिया का दूसरा प्रोग्राम जल्द होगा लांच, इन सेगमेंट्स पर होगा जोर

नई दिल्ली 12 जनवरी (ए)। मोदी सरकार मेक इन इंडिया प्रोग्राम का दूसरा चरण अगले महीने लागू कर सकती है। दूसरे चरण के लिए पांच साल का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। मेक इन इंडिया के दूसरे चरण में रोबॉटिक्स, जीनोमिक्स, केमिकल फीडस्टॉक और इलेक्ट्रिकल स्टोरेज जैसे सेगमेंट्स पर जोर होगा। बता दें, मोदी सरकार ने सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था। उस वक्त ऑटोमोबाइल, टेक्स्टाइल्स, कंस्ट्रक्शन और एविएशन सहित 25 सेक्टरों पर फोक्स किया गया था। इस वक्त सरकार का मकसद लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और रोजगार के मौके बनाना है। दूसरा चरण शुरु होने से पहले का हाल ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हांफती दिख रही है। सरकार का कहना है कि ऐसा ग्लोबल इकॉनमी में सुस्ती के कारण हो रहा है। इस कारण से एक्सपोर्ट डिमांड में गिरावट आई है। देखना होगा कि दूसरे चरण के लिए सरकार किस तरह से खास तैयारियां करती है।

एक सरकारी अधिकारी का कहना था कि, हम चाहते हैं कि Make In India के तहत भविष्य की बातों पर ज्यादा जोर दिया जाए और कुछ सालों में व्यापारी स्तर पर आने वाले अवसरों के लिए हम तैयार हो सकें। अधिकारी के मुताबिक नए चरण के लिए रणनीति बनाई जाएंगी, नई समितियां नहीं बनाई जाएंगी। आकंडों के मुताबिक साल 2017-18 में देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 4.6 पर्सेंट रहने की उम्मीद है।

फ्री में पाएं ऐमजॉन की प्राइम मेंबरशिप

नई दिल्ली 12 जनवरी (ए)। अगर आप भी ऐमजॉन की प्राइम मेंबरशिप को फ्री में लेना चाहते हैं तो इसके लिए एक ऑफर आया है। दरअसल, देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी एयरटेल और ई-कॉमर्स वेबसाइट ऐमजॉन के बीच पार्टनरशिप हुई है, जिसके चलते यह ऑफर दिया जा रहा है। ऐमजॉन की फ्री मेंबरशिप के लिए वैसे तो 999 रुपये देने होते हैं, इसका फायदा यह होता है कि मंगाए गए सामान पर डिलिवरी चार्ज नहीं देना होता और ज्यादातर सामान एक दिन में आ भी जाता है। इतना ही नहीं मेंबरशिप की वजह से प्राइम विडियो पर जाकर फ्री में फिल्में, टीवी शो देखे जा सकते हैं। वहां कुछ सामग्री तो ऐसी होती हैं जो आपको कहीं और देखने को मिलेगी ही नहीं।

कृषि उपकरणों और हरित वाहनों पर घटा सकती है दरें, जीएसटी परिषद करेगी फैसला

नई दिल्ली 12 जनवरी (ए)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद अगले हफ्ते होने वाली अपनी बैठक में बायो-डीजल बसों, इलेक्ट्रिक वाहनों और सिंचाई के कुछ उपकरणों जैसे कुछ वस्तुओं पर कर की दरों में कटौती कर सकती है। इस कदम का मकसद कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ ही स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। । फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से पहले संभवतः यह जीएसटी परिषद की अंतिम बैठक होगी। दरों में कटौती के लिए अपेक्षाकृत छोटी सूची को इस हफ्ते फिटमेंट समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया था जिस पर केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की बैठक में निर्णय लिया जा सकता है।

मामले के जानकार राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं को ही परिषद की आगामी बैठक में दरें घटाने के लिए चुना गया है। 28 फीसदी कर दायरे वाली अन्य वस्तुओं पर इस बार विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि राजस्व संग्रह में अभी स्थिरता नहीं आई है। सिंचाई उपकरणों की दरें 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी की जा सकती है, वहीं बायो-डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों पर दरें 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की जा सकती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम अनुमान में वित्त वर्ष 2018 में कृषि क्षेत्र की विकास दर घटकर 2.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। रबी फसलों के उत्पादन में गिरावट की उम्मीद और खरीफ की पैदावार करीब 3 फीसदी घटने की वजह से कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन पर असर पड़ने का अनुमान लगाया गया है।

घर खरीदारों को नहीं मिल रहा रेरा का फायदा

नई दिल्ली 12 जनवरी (ए)। लाखों घर खरीदारों को बिल्डर्स के झांसे से बचाने के लिए मोदी सरकार द्वारा लाए गए रियल एस्टेट रेग्युलेशन एक्ट (रेरा) का असर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। रेरा को रियल एस्टेट मार्केट में ट्रांसपेरेंसी के मकसद से लागू किया गया, लेकिन ज्यादातर राज्यों में रेरा ढंग से लागू नहीं हो पाया है। यहां तक कि देश के आठ बड़े शहरों में से केवल दो में पूरी ट्रांसपेरेंसी है, बाकी 6 शहरों में ट्रांसपेरेंसी स्कोर न के बराबर है। यह बात रियल एस्टेट कंसलटेंसी फर्म नाइट फ्रैंक, इंडिया के सर्वे में यह ट्रांसपेरेंसी स्कोर जारी किए गए।

15 पैरामीटर की स्टडी: रिपोर्ट में रेरा ट्रांसपेरेंसी स्कोर (मैक्सिमम 15) में मुंबई और पुणे सबसे ऊपर है। मुंबई और पुणे को 15 अंक दिए गए हैं। जबकि दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद और कोलकाता में रेरा ट्रांसपेरेंसी स्कोर जीरो है। दूसरे नंबर पर चेन्नई है, जिसे 13 अंक दिए गए हैं, इसके अलावा नोएडा को 11, अहमदाबाद को 10 और बेंगलुरु को 6 अंक दिए गए हैं।

ये हैं पैरामीटर : स्टडी रिपोर्ट में 15 पैरामीटर तैयार किए गए। हर पैरामीटर को एक अंक दिया गया। इसमें प्रोजेक्ट लेवल इंफॉर्मेशन को प्राथमिकता दी गई, जिसके पैरामीटर में प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट टाइप, लोकेशन, कारपेट एरिया, यूनिट के कुल नंबर, कंफिग्रेशन, नंबर ऑफ बुक फ्लैट, स्टेट्स, कम्पलीशन डेट शामिल हैं। इसके अलावा प्रमोटर (डेवलपर) के बारे में दी गई इंफॉर्मेशन को दूसरा हिस्सा बनाया गया है। इसमें पूछा गया, प्रमोटर नाम, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, पिछले अनुभव के अलावा टाइटिल रिपोर्ट, कोई लीगल रुकावट और प्रोजेक्ट अप्रूवल को पैरामीटर बनाया गया है। इसमें लीगल डिटेल के साथ यह भी जांच की गई कि डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं या नहीं।

सभी पैरामीटर में फिसड्डी रहे ये शहर: इन 15 पैरामीटर में से एक भी पैरामीटर पर दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद और कोलकाता फिसड्डी साबित रहे। दरअसल दिल्ली, केंद्र शासित राज्य होने के कारण केंद्र ने एंटरप्रिस रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी तो बना दी है, लेकिन उससे आगे कोई काम नहीं हुआ है। इसी तरह हरियाणा में रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी तो बन गई है, लेकिन वेबसाइट न होने के कारण ट्रांसपेरेंसी स्कोर जीरो है। पश्चिम बंगाल ने रेरा को लागू करने से इंकार कर दिया है।

भारत ने माल्या के जल्द प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन का मांगा सहयोग

लंदन 12 जनवरी (ए)। भारत ने भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के जल्द प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन से सहयोग मांगा। वहीं माल्या प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई के लिए वेस्ट मिंस्टर मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ। धोखाधड़ी और 9000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में माल्या के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन में कानूनी प्रक्रिया जारी है। ब्रिटेन के सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक क्राइम मामलों के मंत्री बेन वैलेस के साथ द्विपक्षीय बैठक में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहे प्रत्यर्पण के मामले से जुड़ी जानकारी ली। एक अधिकारी ने बताया कि द्विपक्षीय बातचीत के दौरान रिजिजू ने माल्या, आई.पी.एल. के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी, क्रिकेट बुकी संजीव कपूर समेत 13 लोगों के प्रत्यर्पण में ब्रिटेन से सहयोग की गुजारिश की। भारत ने इनके अलावा 16 अन्य कथित अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में ब्रिटेन का सहयोग मांगा। रिजिजू ने अपने ब्रिटिश समकक्ष से यह भी कहा कि ब्रिटेन अपनी धरती का कश्मीरियों और खालिस्तानी अलगाववादियों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल न होने दे।

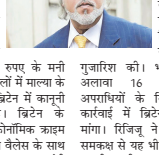

विदेशी सामान की आवाजाही होगी आसान, 300 ड्राई पोर्ट का बदलेगा रंग-रूप

नई दिल्ली 12 जनवरी (ए)। देश के फॉरन ट्रेड को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी मुश्किलों को दूर करने के मकसद से सरकार लगभग 300 ड्राई पोर्ट को ओवरहॉल करेगी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ड्राई पोर्ट से जुड़े कानूनों, उन्हें मिलने वाली सब्सिडी और फंडिंग के पैटर्न के आकलन और उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने बताया, हम ड्राई पोर्ट के लिए रेग्युलेटरी मैकेनिज्म का आकलन कर रहे हैं। इनमें उनसे जुड़े कानून और पोर्ट का कामकाज शामिल है।

आकलन में ड्राई पोर्ट कहे जाने वाले इनलैंड कंटेनर डिपो की तुलना लगभग 10 देशों में इस तरह के पोर्ट के कामकाज से की जाएगी। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत देश में पोर्ट का डिवेलपमेंट करने का लक्ष्य है। ड्राइड्ज, कंटेनर फ्रेट स्टेशंस और एयर फ्रेट स्टेशंस में अधिक दिलचस्पी को देखते हुए यह स्टडी की जा रही है। सागरमाला प्रोजेक्ट की लागत 8 लाख करोड़ रुपये की है। दिल्ली के एक ट्रेड एक्सपर्ट ने बताया, एक ड्राई पोर्ट डिवेलप करने की कॉस्ट अधिक होती है। इन पोर्ट पर कार्गो के

मूवमेंट की प्रक्रिया पुरानी हो चुकी है। इसके लिए कई डिपार्टमेंट से क्लीयरेंस भी लेनी पड़ती हैं। ड्राई पोर्ट एक इनलैंड टर्मिनल होता है जो इंटरनेशनल फ्रेट के लिए हैंडलिंग, टेम्परेरी स्टोरेज, इंस्पेक्शन और कस्टम्स क्लीयरेंस जैसी सर्विसेज दी जाती हैं। ये पोर्ट आमतौर पर ऐसी जगहों पर होते हैं जहां ट्रांसपोर्ट के विभिन्न जरिए मिलते हैं। यह रेल या रोड के जरिए समुद्री पोर्ट से सीधा जुड़ा होता है। इस कदम से फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्टडी में ट्रेड से जुड़ी ट्रांजैक्शन कॉस्ट का विश्लेषण भी किया जाएगा। इसके जरिए लोकेशन और लॉजिस्टिक्स मिक्स के आधार पर नए ड्राई पोर्ट बनाने का भी लक्ष्य है। नवंबर में देश का एक्सपोर्ट एक वर्ष पहले के इसी महीने की तुलना में 30 पर्सेंट बढ़ा था। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2017-18 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 300 अरब डॉलर से कम रह सकता है। 2016-17 में देश का एक्सपोर्ट 274.6 अरब डॉलर का था।